

आय कर अधिकारी, कालीकट

बनाम

श्रीमती एन. के. शारदा थम्पट्टी

सितंबर 14, 1990

[न्यायाधिपति के. एन. सिंह, न्यायाधिपति के. जगन्नाथ शेट्टी और
न्यायाधिपति कुलदीप सिंह]

आयकर अधिनियम, 1961-धारा 171-मूल्यांकन का दायरा-हिंदू अविभाजित परिवार-निर्माण-निर्धारिती द्वारा ली गई विभाजन की याचिका-आयकर अधिकारी के कर्तव्यों का संकेत दिया गया है।

आयकर अधिनियम, 1961-धारा 171, स्पष्टीकरण- "विभाजन" का प्रबंधन और विधायी इरादा आयकर अधिनियम, 1961-धारा 171, स्पष्टीकरण-विभाजन का दावा करने वाला निर्धारिती पर हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में व्यवधान साबित करने का दायित्व है।

आयकर अधिनियम, 1961-धारा 171, स्पष्टीकरण-विभाजन और हिंदू कानून विभाजन-विभेदित।

आयकर अधिनियम, 1961-धारा 171, स्पष्टीकरण-विभाजन का दावा करने वाला निर्धारिती-संपत्तियों का कोई भौतिक विभाजन नहीं, हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति बाधित नहीं-संपत्तियों से प्राप्त आय हिन्दू

अविभाजित परिवार चरित्र से प्रभावित होती रहेगी और उस पर कर लगाया जा सकता है।

प्रतिवादी को हिन्दू अविभाजित परिवार का प्रमुख मानते हुए 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के मूल्यांकन वर्षों के लिए मूल्यांकन किया गया था। उसने आयकर अधिकारी के समक्ष दलील दी कि विभाजन समझौते दिनांक 3.7.1958 के तहत तवाज़ी को विभाजित किया गया था, विभाजन के मुकदमे में सिविल न्यायालय के फैसले के कारण तवाज़ी की हिन्दू अविभाजित परिवार स्थिति बाधित हो गई थी और संपत्तियों को 14 शेयरों में विभाजित किया गया था और हिन्दू अविभाजित परिवार का आयकर निर्धारण नहीं किया जा सका। आयकर अधिकारी ने प्रतिवादी के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सिविल न्यायालय की प्रारंभिक डिक्री के बाद से, और अंतिम नहीं हुआ और कोई भौतिक या वास्तविक विभाजन नहीं हुआ है; कर के उद्देश्य से हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति जारी रही।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी की रिट याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि आयकर अधिनियम की धारा 171 ऐसे मामले पर लागू नहीं होती है जहां लेखांकन अवधि शुरू होने से पहले विभाजन किया गया था और लेखांकन अवधि के दौरान हिन्दू अविभाजित परिवार को कोई आय प्राप्त नहीं हुई थी। धारा 171 के तहत कानूनी कल्पना के बावजूद इस पर कर का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अपील में

खण्डपीठ ने माना कि धारा 171 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था और न ही धारा के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाला कोई आवश्यक निहितार्थ था कि इसके बाद परिवार की आय संयुक्त स्थिति में व्यवधान के बावजूद विभाजन को हिन्दू अविभाजित परिवार की आय माना जाना चाहिए या समझा जाना चाहिए। बेंच ने कहा कि एचयूएफ सदस्यों से एक अलग और विशिष्ट इकाई है। इसका गठन करते समय और यदि उस इकाई को कोई आय प्राप्त नहीं होती है, तो सदस्यों की आय का मूल्यांकन हिन्दू अविभाजित परिवार की आय के रूप में नहीं किया जाएगा। खंड पीठ ने आगे कहा कि चूंकि परिवार में विभाजन हो चुका था और तवाज़ी लेखांकन अवधि से बहुत पहले हिन्दू अविभाजित परिवार नहीं रह गया था, इसलिए परिवार के व्यक्तिगत सदस्यों की आय पर कर लगाने के उद्देश्य से अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता था। अधिनियम की धारा 171 की सहायता से उन्हें हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति प्रदान करना।

उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत राजस्व को प्रमाण पत्र प्रदान किया, इसलिए ये अपीलें हैं।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1. धारा 171 के तहत एक हिंदू परिवार का मूल्यांकन हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में किया जाता है। अधिनियम के प्रयोजनों के लिए हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में जारी रखने के लिए समझा जाता है, सिवाय इसके कि जहां अनुभाग के अनुसार विभाजन प्रभावी साबित

हुआ हो। अनुभाग में आगे प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति मूल्यांकन के समय दावा करता है कि विभाजन कुल या आंशिक हुआ है हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों के बीच, आयकर अधिकारी को परिवार के सभी सदस्यों को नोटिस देकर पूछताछ करने और विभाजन के प्रश्न पर निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होती है। यदि पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि बंटवारा हो गया है, तो सदस्यों की व्यक्तिगत देनदारी की गणना उन्हें आवंटित संयुक्त परिवार की संपत्ति के हिस्से के अनुसार की जाएगी।

2. विभाजन की परिभाषा किसी विभाजन को मान्यता नहीं देती है, भले ही वह अदालत के आदेश से हुआ हो, जब तक कि संपत्ति का भौतिक विभाजन न हो और यदि संपत्ति भौतिक रूप से विभाजित होने में सक्षम नहीं है, तो संपत्ति का विभाजन होना चाहिए। अन्यथा यह किस सीमा तक संभव है। स्थिति का विच्छेद विभाजन नहीं माना जाएगा। मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए विभाजन के तथ्य पर विचार करते समय स्पष्टीकरण के तहत विभाजन को दिए गए विशेष अर्थ को नजरअंदाज करना स्वीकार्य नहीं है, भले ही विभाजन अदालत के डिक्री के माध्यम से किया गया हो। आमतौर पर विभाजन के मुकदमे में सिविल कोर्ट की डिक्री विभाजन के सबूत में अच्छा सबूत है, लेकिन धारा 171 के तहत एक कानूनी कल्पना पेश की गई है जिसके अनुसार विभाजन की प्रारंभिक डिक्री है पर्याप्त नहीं, इसके बजाय अंतिम डिक्री के अनुसार, सीमा और सीमा के अनुसार संपत्ति

का वास्तविक भौतिक विभाजन होना चाहिए। विधानमंडल ने राजस्व के हितों की रक्षा की दृष्टि से उपरोक्त स्पष्टीकरण के तहत विभाजन को एक विशेष अर्थ दिया है।

3. हिंदू अविभाजित परिवार के विभाजन का दावा करने वाले किसी भी निर्धारिती को स्पष्टीकरण को विशेष ध्यान में रखते हुए धारा 171 के प्रावधानों के अनुसार एचयूएफ की स्थिति में व्यवधान को साबित करना होगा। निर्धारिती को यह साबित करना होगा कि समझौते या अदालत के आदेश के माध्यम से हुए विभाजन के बाद संपत्ति का वास्तविक भौतिक विभाजन हुआ। ऐसे सबूत के अभाव में कर निर्धारण के उद्देश्य से विभाजन हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

4. हिंदू कानून के तहत संयुक्त परिवार के सदस्य निजी समझौते, समझौते, मध्यस्थता या अदालत के डिक्री के माध्यम से संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए सहमत हो सकते हैं। परिवार के सदस्य संपत्ति से होने वाली आय को अपने-अपने हिस्से के अनुसार साझा करने के लिए भी सहमत हो सकते हैं। ऐसी सभी स्थितियों में परिवार की संयुक्त स्थिति बाधित हो सकती है, लेकिन आयकर के प्रयोजनों के लिए पारिवारिक स्थिति में इस तरह के व्यवधान को विधायिका द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। अधिनियम की धारा 171 और उसका स्पष्टीकरण, विभाजन का एक विशेष अर्थ निर्धारित करता है जो हिंदू कानून के सामान्य सिद्धांतों से

अलग है। इसमें एक डीमिंग प्रावधान शामिल है जिसके तहत एचयूएफ की संपत्ति का विभाजन केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब संपत्ति का वास्तविक भौतिक विभाजन हुआ हो, ऐसे किसी भी सबूत के अभाव में, एचयूएफ को कर के मूल्यांकन के उद्देश्य से जारी माना जाएगा। संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन को प्रभावित करने वाला कोई भी समझौता, या विभाजन के लिए न्यायालय की डिक्री की स्थिति को समाप्त नहीं किया जा सकता है। एचयूएफ जब तक यह न दिखाया जाए कि संयुक्त परिवार की संपत्ति को न्यायालय के समझौते या डिक्री के अनुसार भौतिक रूप से विभाजित किया गया था।

5. प्रतिवादी ने पहली बार कार्यवाही में एचयूएफ के विभाजन और व्यवधान की दलील उठाई। मूल्यांकन वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के लिए। सीमाओं और सीमाओं के आधार पर संपत्तियों का कोई भौतिक विभाजन नहीं किया गया था। एचयूएफ की स्थिति बाधित नहीं हुई थी और मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए संपत्तियों से प्राप्त आय एचयूएफ चरित्र से प्रभावित रही।

परमेश्वरन नम्बूदिरीपद बनाम सहायक आयुक्तों का निरीक्षण कृषि आयकर विभाग के निदेशक, 72 आई. टी. आर 644; सहायक कृषि आयकर और बिक्री कर आयुक्त (विशेष) कोझिकोड बनाम पूमुल्ली मानेक्कल परमेश्वरन नम्बूदिरीपाद 83 आई. टी. आर 108, विशिष्ट।

कालूमल तपेश्वर प्रसाद बनाम सी. आई. टी. कानपुर, 133 आई. टी. आर. 690 का अनुसरण किया।

सुंदर सिंह मजीठिया बनाम आयकर आयुक्त, [1942] 10आई. टी. आर 457 शंकर नारायणन बनाम आयकर अधिकारी, 153 आई. टी. आर. 562, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 778 और 781/1976

1973 की रिट अपील संख्या 126 और 378 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 30.6.1975 और 8.8.1975 से

वी. गौरीशंकर, एस. राजप्पा और सुश्री ए. सुभाशिनी अपीलार्थी के लिए।

जी. विश्वनाथ अय्यर, श्रीमती के. प्रशांति और एन. सुधाकरन उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति सिंह

संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर ये अपीलें केरल उच्च न्यायालय के आदेश और निर्णय के खिलाफ निर्देशित हैं।

संक्षेप में, इन अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं: प्रतिवादी मद्रास मरुमक्कथ्यम अधिनियम द्वारा शासित पूर्ववर्ती नीलांबुत कोविलगम की सदस्य थी, उस पर हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में आयकर का निर्धारण किया गया था क्योंकि परिवार के पास भूमि, जंगल और अन्य संपत्तियों सहित काफी संपत्ति थी। . आयकर अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के लिए एचयूएफ के भीतर शामिल परिवार के सदस्यों का देखते हुए प्रतिवादी का मूल्यांकन किया। आयकर अधिकारी के समक्ष, प्रतिवादी ने एक दलील दी, कि 3.7.1958 के एक विभाजन समझौते के तहत तवाज़ी का विभाजन किया गया था, जिसके तहत वन भूमि को छोड़कर सभी भूमि परिवार के सदस्यों के बीच विभाजित की गई थी। प्रतिवादी ने आगे दावा किया कि तवाज़ी के सदस्य बढ़कर 14 हो गए और इन सदस्यों ने दिनांक 21.2.1963 को एक पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा स्थिति में विभाजन किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि तवाज़ी का 14 शेयरों में विभाजन कोझिकोड की अदालत में विभाजन वाद संख्या ओएस 22/1961 में सिविल कोर्ट के डिक्री द्वारा प्रभावित किया गया था। प्रतिवादी की ओर से यह बताया गया कि विभाजन के मुकदमे का फैसला किया गया था और संपत्तियां संबंधित शेयर धारकों को आवंटित की गई थीं। सिविल कोर्ट ने व्यक्तिगत सदस्यों के शेयरों के अनुसार संपत्ति को सीमा और सीमा के अनुसार विभाजित करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया था। प्रतिवादी ने आगे दावा किया कि चूंकि विभाजन के फैसले के कारण एचयूएफ की स्थिति बाधित हो गई थी,

इसलिए एचयूएफ का आयकर के लिए मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था, इसके बजाय व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्राप्त आय पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जा सकता था।

आयकर अधिकारी ने प्रतिवादी के दावे को खारिज कर दिया और अपने आदेश दिनांक 16.3.1970/ 27.3.1970 द्वारा मूल्यांकन वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के लिए तवाज़ी के प्रमुख के रूप में प्रतिवादी का मूल्यांकन किया। आयकर अधिकारी ने माना कि सिविल न्यायालय की डिक्री ने परिवार के सदस्यों को भौतिक विभाजन के बाद उनके हिस्से में आने वाली भूमि पर अलग-अलग कब्जा करने का अधिकार प्रदान किया है, और अंतिम विभाजन व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा किए गए आवेदन पर किया जा सकता है। आयुक्त का शुल्क जमा करना। चूंकि सिविल न्यायालय की डिक्री एक प्रारंभिक डिक्री थी और कोई अंतिम डिक्री पारित नहीं की गई थी और कोई वास्तविक विभाजन नहीं किया गया था और विभाजन की डिक्री के अनुसरण में मेट और सीमा द्वारा कोई भौतिक विभाजन नहीं हुआ था, एचयूएफ की स्थिति मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए जारी रही। आयकर अधिकारी ने पाया कि पहले करदाता का मूल्यांकन एचयूएफ की स्थिति के आधार पर किया गया था, और चूंकि कोई अन्य सबूत नहीं था

सिवाय इसके कि सिविल न्यायालय की डिक्री यह दिखाने के लिए प्रस्तुत की गई थी कि वास्तविक विभाजन हुआ है, इसलिए, विभाजन के लिए निर्धारिती का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी ने आयकर

अधिकारी के आदेशों को इस आधार पर रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की कि वह मूल्यांकन करने में एचयूएफ के व्यवधान को पहचानने में विफल रहा। उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और मूल्यांकन आदेशों को रद्द कर दिया। राजस्व के अनुरोध पर अपील पर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की। राजस्व की ओर से किए गए आवेदन पर उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसलिए ये अपीलें हैं।

विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि आयकर अधिनियम की धारा 171 ऐसे मामले पर लागू नहीं होती है जहां लेखांकन अवधि शुरू होने से पहले विभाजन किया गया था, और एचयूएफ को लेखांकन अवधि के दौरान कोई आय प्राप्त नहीं हुई थी, इसके बावजूद कर का आकलन नहीं किया जा सकता था। धारा 171 द्वारा पेश की गई कल्पना। अपील में डिवीजन बेंच ने माना कि धारा 171 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था और न ही धारा के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाला कोई आवश्यक निहितार्थ था कि विभाजन के बाद परिवार की आय को माना जाना चाहिए या माना जाना चाहिए संयुक्त स्थिति में व्यवधान के बावजूद एचयूएफ की आय का आकलन करें। खंडपीठ ने कहा कि एक एचयूएफ इसे बनाने वाले सदस्यों से एक अलग और विशिष्ट इकाई है और यदि उस इकाई को कोई आय प्राप्त नहीं होती है,

तो सदस्यों की आय का आकलन एचयूएफ की आय के रूप में नहीं किया जा सकता है। . डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि चूंकि परिवार में विभाजन हो गया था और तवाजी लेखांकन अवधि से बहुत पहले एचयूएफ नहीं रह गया था, इसलिए अधिनियम के प्रावधानों को व्यक्तिगत सदस्यों की आय पर कर लगाने के उद्देश्य से लागू नहीं किया जा सकता था। अधिनियम की धारा 171 की सहायता से परिवार उनके साथ एचयूएफ का दर्जा रखता है।

मुख्य प्रश्न जो विचाराधीन है वह यह है कि क्या दिनांक 21.2.1963 के समझौते और सिविल कोर्ट के आदेश के अनुसार विभाजन अधिनियम की धारा 171 के स्पष्टीकरण के तहत "विभाजन" के बराबर है और आगे क्या आयकर अधिकारी ने यह मानते हुए कानून के विपरीत काम किया कि प्रतिवादी द्वारा कथित विभाजन के बावजूद, एचयूएफ की स्थिति बाधित नहीं हुई और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्षों के दौरान मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए वह स्थिति जारी रही। धारा 171 के तहत एचयूएफ के रूप में मूल्यांकन किए गए एक हिंदू परिवार को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एचयूएफ के रूप में जारी रखने के लिए माना जाता है, सिवाय इसके कि जहां अनुभाग के अनुसार विभाजन प्रभावी साबित हुआ हो। धारा में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति मूल्यांकन के समय यह दावा करता है कि एचयूएफ के सदस्यों के बीच पूर्ण या आंशिक विभाजन हुआ है। आयकर अधिकारी को परिवार के सभी सदस्यों को नोटिस देकर पूछताछ करने और विभाजन के प्रश्न पर निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता होती है। यदि

पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि बंटवारा हो गया है, तो सदस्यों की व्यक्तिगत देनदारी की गणना उन्हें आवंटित संयुक्त परिवार की संपत्ति के हिस्से के अनुसार की जाएगी। अनुभाग के प्रयोजनों के लिए विभाजन की राशि क्या होगी, यह अनुभाग के स्पष्टीकरण में निहित है जो विभाजन को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"स्पष्टीकरण-इस खंड में-

(ए) 'विभाजन' का अर्थ है (i) जहां संपत्ति भौतिक विभाजन को स्वीकार करती है, वहां संपत्ति का भौतिक विभाजन होता है, लेकिन आय का उत्पादन करने वाली संपत्ति के भौतिक विभाजन के बिना आय का भौतिक विभाजन विभाजन नहीं माना जाएगा। ; या

(ii) जहां संपत्ति भौतिक विभाजन को स्वीकार नहीं करती है, तो ऐसे विभाजन को संपत्ति स्वीकार करती है, लेकिन केवल स्थिति का विच्छेद विभाजन नहीं माना जाएगा।"

विभाजन की उपरोक्त परिभाषा विभाजन को मान्यता नहीं देती है

भले ही यह अदालत की डिक्री द्वारा प्रभावी हो, जब तक कि कोई भौतिक न हो

संपत्ति का विभाजन और यदि संपत्ति भौतिक रूप से विभाजित होने में सक्षम नहीं है तो संपत्ति का विभाजन उस सीमा तक होना चाहिए जहां तक संभव हो अन्यथा स्थिति का विच्छेद विभाजन नहीं होगा। मूल्यांकन के

प्रयोजनों के लिए विभाजन के तथ्य पर विचार करते हुए, स्पष्टीकरण के तहत विभाजन को दिए गए विशेष अर्थ को नजरअंदाज करना स्वीकार्य नहीं है, भले ही विभाजन अदालत के डिक्री के माध्यम से किया गया हो। आमतौर पर विभाजन के मुकदमे में सिविल कोर्ट की डिक्री विभाजन के सबूत में अच्छा सबूत है, लेकिन धारा 171 के तहत एक कानूनी कल्पना पेश की गई है जिसके अनुसार विभाजन की प्रारंभिक डिक्री पर्याप्त नहीं है, इसके बजाय संपत्ति का वास्तविक भौतिक विभाजन होना चाहिए। परिधि और सीमा द्वारा अंतिम डिक्री के लिए। विधानमंडल ने राजस्व के हितों की रक्षा की दृष्टि से उपरोक्त स्पष्टीकरण के तहत विभाजन को विशेष अर्थ दिया है। एचयूएफ के विभाजन का दावा करने वाले किसी भी निर्धारिती को स्पष्टीकरण को विशेष ध्यान में रखते हुए धारा 171 के प्रावधानों के अनुसार एचयूएफ की स्थिति में व्यवधान को साबित करना होगा। निर्धारिती को यह साबित करना होगा कि समझौते से या अदालत के आदेश के माध्यम से हुआ विभाजन, वास्तविक भौतिक विभाजन के बाद हुआ था। ऐसे सबूत के अभाव में संपत्ति का विभाजन कर निर्धारण के उद्देश्य से हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हिंदू कानून के तहत संयुक्त परिवार के सदस्य निजी समझौते, समझौते, मध्यस्थता या अदालत के डिक्री के माध्यम से संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के लिए सहमत हो सकते हैं। परिवार के सदस्य संपत्ति से होने वाली आय को अपने-अपने हिस्से के अनुसार बांटने पर भी सहमत हो सकते हैं। ऐसी सभी स्थितियों में परिवार की संयुक्त स्थिति बाधित हो

सकती है, लेकिन पारिवारिक स्थिति में इस तरह के व्यवधान को आयकर के प्रयोजनों के लिए विधायिका द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। अधिनियम की धारा 171 और इसकी व्याख्या, विभाजन का एक विशेष अर्थ बताती है जो हिंदू कानून के सामान्य सिद्धांतों से अलग है। इसमें एक प्रावधान है जिसके तहत एचयूएफ की संपत्ति का विभाजन केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब वास्तविक भौतिक विभाजन हुआ हो। संपत्ति के मामले में, ऐसे किसी सबूत के अभाव में, एचयूएफ को कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए जारी माना जाएगा। संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच विभाजन को प्रभावित करने वाला कोई भी समझौता, या विभाजन के लिए न्यायालय की डिक्री एचयूएफ की स्थिति को समाप्त नहीं कर सकती है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति न्यायालय के समझौते या डिक्री के अनुसार भौतिक रूप से विभाजित की गई थी।

प्रतिवादी की ओर से यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया है परमेश्वरन नंबूदरीपाद बनाम निरीक्षण सहायक कृषि आयकर आयुक्त, 72 आई.टी.आर. 664 जहां यह माना गया कि यदि एचयूएफ वास्तव में लेखांकन अवधि के किसी भी भाग के दौरान अस्तित्व में नहीं था, और एचयूएफ को कोई आय प्राप्त नहीं हुई थी, तो परिवार पर एचयूएफ के रूप में कर का निर्धारण नहीं किया जा सकता था। कृषि आयकर और बिक्री कर (विशेष), कोझिकोड बनाम पूमुली मानेक्कल परमेश्वरन नंबूदरीपाद, 33

आईटीआर 108 के सहायक आयुक्त के निरीक्षण में इस न्यायालय द्वारा पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी गई है। इस न्यायालय के फैसले की सावधानीपूर्वक जांच करने पर हम पाते हैं कि उस मामले में 1964 में संशोधित केरल कृषि आयकर अधिनियम 1950 की धारा 29 की व्याख्या शामिल थी। 1964 में संशोधन के बाद धारा 29 में हिंदू अविभाजित परिवार के विभाजन के बाद कृषि कर के आकलन का प्रावधान किया गया। उस धारा के तहत आयकर अधिनियम की धारा 171 के स्पष्टीकरण की प्रकृति में कोई प्रावधान नहीं था। इस न्यायालय के पास धारा 171 की व्याख्या करने का कोई अवसर नहीं था, इसके बजाय न्यायालय ने उस अधिनियम की धारा 29 की व्याख्या की, जो धारा 171 से बिल्कुल अलग है, इसलिए अपीलकर्ता उस निर्णय से कोई समर्थन नहीं ले सकता। कालूमल तपेश्वर प्रसाद बनाम सी.एल. टी. कानपुर, 133 आई.टी.आर. 690 इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 171 की विस्तार से व्याख्या की। विस्तृत चर्चा के बाद न्यायालय ने माना कि हिंदू कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि विभाजन को पूरा करने के लिए संपत्ति को हर मामले में सीमा और भौतिक रूप से अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया जाना चाहिए। स्थिति में व्यवधान हिंदू कानून के तहत स्वीकार्य किसी भी तरीके से लाया जा सकता है और यह पार्टियों के लिए अपनी इच्छा के अनुसार कानून द्वारा ज्ञात किसी भी तरीके से संपत्ति के अपने हिस्से का आनंद लेने के लिए खुला है, लेकिन आयकर कानून किसी भी तरीके को स्वीकार नहीं करता है। कर के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए इस तरह के विभाजन के

बजाय इसने अधिनियम की धारा 171 के तहत विभाजन को प्रभावी बनाने के लिए अपनी कुछ शर्तें पेश की हैं। न्यायालय ने माना कि विभाजन के आधार पर हिंदू अविभाजित परिवार में व्यवधान का दावा करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि विभाजन भौतिक रूप से परिधि और सीमा के कारण हुआ था, और ऐसे किसी भी सबूत के अभाव में, संपत्ति को संपत्ति के रूप में माना जाता रहेगा। हिंदू अविभाजित परिवार से संबंधित और इसकी आय निर्धारिती को हिंदू अविभाजित परिवार मानते हुए इसकी कुल आय में शामिल की जाती रहेगी।

उच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम 1922 की धारा 25 ए का उल्लेख किया और कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि विभाजन के लिए सिविल न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति बाधित हो गई थी और चूंकि इस पर कोई सबूत नहीं था। यह दिखाने के लिए कि हिंदू अविभाजित परिवार को लेखांकन वर्ष में कोई आय प्राप्त हुई थी, संयुक्त परिवार के व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्राप्त आय को हिंदू अविभाजित परिवार की आय नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने सुंदर सिंह मजीठिया बनाम आयकर आयुक्त, [1942] आईओ आईटीआर 457 और कई अन्य निर्णयों में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर भरोसा जताया और कहा कि अधिनियम की धारा 171 के तहत पेश की गई कानूनी कल्पना नहीं की जा सकती। विभाजन के लिए सिविल न्यायालय के फैसले के अनुसार, हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति में व्यवधान के बाद भी

उस पर कर देनदारी बनाने के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। हम उन निर्णयों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं समझते हैं, क्योंकि धारा 171 के उद्देश्य और उद्देश्य और इसके द्वारा पेश की गई कानूनी कल्पना की सीमा पर कालूमल के मामले में इस न्यायालय द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है। आक्षेपित निर्णय के तहत उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह उस निर्णय के विपरीत है। शंकर नारायणन बनाम आयकर अधिकारी 153 आई टी आर 562 में केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने धारा 171 की व्याख्या पर विचार करते हुए यह माना कि निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण। अपील आयकर अधिकारी, मूल्यांकन वी, कालीकट बनाम श्रीमती एन.के. सारदा थम्पट्टी, 150 आई.टी.आर. 67 कालूमल के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर अच्छा कानून नहीं रहा।

मौजूदा मामले में चूंकि कोई विवाद नहीं था कि आकलन वर्ष 1967-68 से पहले मूल्यांकन उस एचयूएफ के खिलाफ किया गया था जिसका प्रतिवादी सदस्य था। प्रतिवादी ने पहली बार मूल्यांकन वर्ष 1967-68, 1968-69 और 1969-70 की कार्यवाही में हिंदू अविभाजित परिवार के विभाजन और व्यवधान की दलील उठाई। आयकर अधिकारी के समक्ष इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं था कि संपत्तियों का परिधि और सीमा के आधार पर कोई भौतिक विभाजन नहीं किया गया था, इसलिए आयकर अधिकारी का यह मानना उचित था कि हिंदू अविभाजित परिवार की

स्थिति बाधित नहीं हुई थी और संपत्तियों से प्राप्त आय मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए हिंदू अविभाजित परिवार के चरित्र से प्रभावित होना जारी रखें। हमारी राय में उच्च न्यायालय ने इसे रद्द करने में गलती की है आयकर अधिकारी का आदेश. परिणामस्वरूप, हम अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हैं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

वी पी

आपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।